हरियाणा राज्य - अधिनियम

हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1971

हरियाणा

भारत

हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1971

1971 का अधिनियम 9

हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1971 1971 का हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 15 मार्च, 1971 को हरियाणा के राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई और पहली बार 18 मार्च, 1971 को हरियाणा सरकार के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुआ।प्रमाणित संस्थान में भिखारियों और उनके आश्रितों की भीख मांगने की रोकथाम, हिरासत, प्रशिक्षण और रोजगार और भिखारी अपराधियों की हिरासत, परीक्षण और सजा का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम।भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा इसे निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाए:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ.

(1)इस अधिनियम को हरियाणा भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम, 1971 कहा जा सकता है।
(2)इसका विस्तार पूरे हरियाणा राज्य तक है।
(3)यह राज्य के किसी भी क्षेत्र में ऐसी तारीख या तिथियों पर लागू होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस क्षेत्र के लिए इस संबंध में नियुक्त कर सकती है।

2. परिभाषाएँ.

- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-
(ए)"भिखारी" का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो भीख मांगते हुए पाया जाता है;
(बी)"भीख माँगना" का अर्थ है -(मैं)किसी सार्वजनिक स्थान पर भिक्षा मांगना या प्राप्त करना, चाहे वह किसी बहाने से हो या नहीं, जैसे गाना, नृत्य करना, भविष्य बताना, करतब दिखाना या वस्तुएँ बेचना;(ii)आजीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन न होना और किसी सार्वजनिक स्थान पर

ऐसी स्थिति या तरीके से घूमना या रहना जिससे यह संभावना हो कि ऐसा करने वाला व्यक्ति भिक्षा मांगकर या प्राप्त करके जीवित रहता है;(iii)भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी निजी परिसर में प्रवेश करना;(iv)भिक्षा प्राप्त करने या जबरन वसूली के उद्देश्य से, किसी घाव, घाव, चोट, विकृति या बीमारी को उजागर करना या प्रदर्शित करना, चाहे वह इंसान का हो या जानवर का; या(v)भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य से स्वयं को एक प्रदर्शनी के रूप में उपयोग करने की अनुमति देना;लेकिन इसमें किसी कानून द्वारा प्राधिकृत या निर्धारित तरीके से प्राधिकृत किसी उद्देश्य के लिए धन या भोजन या उपहार की याचना करना या प्राप्त करना शामिल नहीं है;

(सी)"प्रमाणित संस्थान" का अर्थ है कोई भी संस्थान जिसे राज्य सरकार भिखारियों और उनके आश्रितों की हिरासत, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए प्रदान करती है और बनाए रखती है और इसमें एक प्रमाणित गृह और विशेष गृह शामिल है;

(डी)"प्रमाणित गृह" का अर्थ है राज्य सरकार या उसके द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित घर, जो कुष्ठ रोग या इस संबंध में अधिसूचित किसी अन्य संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित भिखारियों के स्वागत और हिरासत के लिए उपयुक्त स्थान है। राज्य सरकार द्वारा;

(इ)"मुख्य निरीक्षक" का अर्थ धारा 18 के तहत प्रमाणित संस्थानों के मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त व्यक्ति है;

(एफ)"बच्चे" का अर्थ पूर्वी पंजाब बाल अधिनियम, 1949 के तहत परिभाषित व्यक्ति है;

(जी)"न्यायालय" का अर्थ उस क्षेत्र में आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी भी वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है जिसमें यह अधिनियम लागू है;

(एच)"अभिभावक" का अर्थ वह व्यक्ति है जो अपने माता-पिता की अनुपस्थिति में या उनकी मृत्यु की स्थिति में बच्चे की देखभाल करता है या उनकी देखभाल करता है;

(मैं)"कारावास" का अर्थ कठोर या साधारण कारावास है जैसा कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का एक्सएलवी) की धारा 53 में वर्णित है;

(जे)"अभिभावक" का अर्थ है बच्चे का पिता या माता;

(क)"पुलिस अधिकारी" का अर्थ है एक पुलिस अधिकारी जो सहायक उप-निरीक्षक के पद से नीचे न हो;

(एल)"निर्धारित" का अर्थ इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

(एम)"परिवीक्षा अधिकारी" का अर्थ धारा 18 के तहत परिवीक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया अधिकारी है;
(एन)"सार्वजनिक स्थान" का अर्थ है और इसमें कोई भी स्थान या उसका परिसर शामिल है, जहां कुछ समय के लिए जनता को प्रवेश की अनुमति है, चाहे भुगतान पर या अन्यथा और इसमें एक यात्री बस और एक रेलवे कंपार्टमेंट शामिल है;
(ओ)"रिसेप्शन सेंटर" का अर्थ है भिखारियों के स्वागत और अस्थायी हिरासत के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली या धारा 13 के तहत प्रमाणित संस्था;
(पी)"विशेष गृह" का अर्थ राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक घर है जो भिखारियों के स्वागत और हिरासत के लिए उपयुक्त है, जो शारीरिक रूप से शारीरिक श्रम करने में सक्षम नहीं हैं लेकिन कुष्ठ रोग या किसी अन्य संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित नहीं हैं; और
(क्यू)"अधीक्षक" का अर्थ रिसेप्शन सेंटर या प्रमाणित संस्थान, जैसा भी मामला हो, का अधीक्षक है।

3. गिरफ्तार करने की शक्ति.

(1)कोई भी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत अन्य व्यक्ति किसी भी भिखारी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है:बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान के अलावा किसी भी परिसर में भीख मांगते हुए पाया जाए तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा या ऐसे परिसर के कब्जेदार द्वारा की गई शिकायत के अलावा इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(2)ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाएगा या भेज देगा:बशर्ते कि यदि दूसरा व्यक्ति सुविधाजनक समझे तो वह उसे किसी पुलिस अधिकारी को सौंप सकता है।
(3)दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 61 के प्रावधान इस धारा के तहत की गई गिरफ्तारी पर लागू होंगे और पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को निर्धारित तरीके से तब तक हिरासत में रखेंगे जब तक कि उसे सामने नहीं लाया जाता है। एक अदालत।

4. हिरासत से पहले सारांश पूछताछ.

- जहां किसी व्यक्ति को धारा 3 के तहत न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तो न्यायालय इस आरोप के संबंध में निर्धारित तरीके से एक संक्षिप्त जांच करेगा कि उसे भीख मांगते हुए पाया गया था।

(2)यदि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जांच तुरंत पूरी नहीं की जा सकती है, तो न्यायालय इसे समय-समय पर स्थगित कर सकता है और व्यक्ति को ऐसे स्थान और हिरासत में भेजने का आदेश दे सकता है जो सुविधाजनक हो या उसे जमानत बांड पर रिहा कर दे। ज़मानत के साथ या उसके बिना.

(3)यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूछताछ करने पर न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि व्यक्ति भीख मांगते हुए पाया गया तो वह आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत रिहा कर दिया जाए।

(4)यदि, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर, न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति भीख मांगते हुए पाया गया था, तो यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति भिखारी है और तदनुसार उसे दोषी ठहराएगा।

(5)न्यायालय उपधारा (4) के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार एक प्रमाणित संस्थान में कम से कम एक वर्ष और दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश देगा:बशर्ते कि यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति के दोबारा भीख मांगने की संभावना नहीं है, तो वह उसे भीख मांगने से परहेज करने के लिए एक बांड पर उचित चेतावनी के बाद रिहा कर सकता है, जिसे जमानत के साथ या उसके बिना निष्पादित किया जा सकता है, जैसा कि न्यायालय मानता है। उपयुक्त :बशर्ते कि यदि भिखारी नाबालिग है, तो बांड जमानतदारों के साथ होगा।

(6)इस धारा के तहत आदेश पारित करते समय, न्यायालय को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:-

(ए)भिखारी की उम्र और चरित्र;

(बी)भिखारी जिन परिस्थितियों और स्थितियों में रह रहा है;

(सी)परिवीक्षा अधिकारी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट, यदि कोई हो; और

(डी)ऐसे अन्य मामले, जिन पर न्यायालय की राय में भिखारी के हित में विचार करने की आवश्यकता हो।

(7)परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट या न्यायालय द्वारा विचार की गई कोई अन्य रिपोर्ट गोपनीय मानी जाएगी:बशर्ते कि यदि ऐसी रिपोर्ट भिखारी के चरित्र, स्वास्थ्य या आचरण या उन परिस्थितियों और स्थितियों से संबंधित है जिनमें वह रह रहा है, तो न्यायालय यदि ऐसा करना उचित समझे तो भिखारी को उसके सार के बारे में सूचित कर सकता है, या यदि भिखारी है अपने माता-पिता या अभिभावक पर निर्भर, यदि कोई हो, और भिखारी या माता-पिता या अभिभावक

को, जैसा भी मामला हो, साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दे सकता है जो रिपोर्ट में बताए गए मामलों के लिए प्रासंगिक हो सकता है।

(8)उपधारा (5) के तहत दिए गए आदेश की एक प्रति न्यायालय द्वारा मुख्य निरीक्षक को तुरंत भेजी जाएगी।

(9)इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, जब उपरोक्त भिखारी पाया गया व्यक्ति बच्चा है, तो न्यायालय उपधारा (5) के तहत कोई आदेश नहीं देगा, बल्कि बच्चे को पूर्वी पंजाब बाल अधिनियम के तहत गठित न्यायालय को भेज देगा। 1949, उस अधिनियम के तहत निपटाए जाने के लिए। भिखारी की उम्र सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यदि आवश्यक हो, तो न्यायालय उसकी चिकित्सा अधिकारी से जांच करा सकता है।

5. नजरबंदी के बाद भीख मांगने पर जुर्माना.

(1)धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार किसी प्रमाणित संस्थान में पहले हिरासत में लिया गया कोई भी व्यक्ति फिर से भीख मांगते हुए पाया जाता है तो दोषसिद्धि पर दंडनीय होगा जैसा कि इस धारा में इसके बाद प्रावधान किया गया है।

(2)जब किसी व्यक्ति को दूसरी बार दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे कम से कम एक वर्ष और अधिक से अधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए किसी प्रमाणित संस्थान में हिरासत में रखने का आदेश देगा।

(3)जब किसी व्यक्ति को तीसरी या उसके बाद दोषी ठहराया जाता है, तो न्यायालय उसे प्रमाणित संस्थान में पांच साल की अवधि के लिए हिरासत में रखने का आदेश देगा और ऐसी हिरासत की किसी भी अवधि को, एक वर्ष से अधिक नहीं, कारावास की सजा में बदल सकता है:बशर्ते कि हिरासत और कारावास की कुल अवधि, यदि कोई हो, पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

6. आश्रितों को निरुद्ध करने की न्यायालय की शक्ति.

(1)जब न्यायालय ने किसी भिखारी को धारा 4 या धारा 5 के तहत किसी प्रमाणित संस्थान में हिरासत में रखने का आदेश दिया है, तो वह ऐसी जांच करने के बाद जो वह उचित समझे, किसी भी व्यक्ति को, जो ऐसे भिखारी पर पूरी तरह से निर्भर है, प्रमाणित संस्थान में हिरासत में रखने का आदेश दे सकता है। एक समान अवधि:बशर्ते कि ऐसा आदेश देने से पहले ऐसे आश्रित या उसके माता-पिता या अभिभावक, यदि कोई हो, को, जैसा भी मामला हो, कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(2)जहां आश्रित व्यक्ति पांच वर्ष से अधिक आयु का बच्चा है, अदालत उसे पूर्वी पंजाब बाल अधिनियम, 1959 के तहत गठित अदालत में निपटारे के लिए भेज देगी।

7. सुपुर्दगी से पहले चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट.

(1)जो न्यायालय किसी व्यक्ति को धारा 4 या धारा 5 के तहत दोषी पाता है, उसे किसी प्रमाणित संस्थान को उसकी प्रतिबद्धता के बारे में कोई सजा देने से पहले, ऐसे व्यक्ति को स्थानीय सिविल अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल से जुड़े चिकित्सा अधिकारी के पास भेजना होगा। प्रमाणित संस्थान, यदि कोई हो, और उसकी उम्र, सामान्य शारीरिक श्रम के लिए शारीरिक क्षमता और यह भी कि क्या वह किसी संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित है, के बारे में रिपोर्ट मांगे।

(2)यदि चिकित्सा अधिकारी प्रमाणित करता है कि उक्त व्यक्ति बच्चा नहीं है, शारीरिक रूप से सामान्य शारीरिक श्रम करने में सक्षम है और किसी संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित संस्थान को सौंपने के लिए सजा सुनाएगा।

(3)यदि चिकित्सा अधिकारी रिपोर्ट करता है कि उक्त व्यक्ति शारीरिक रूप से सामान्य शारीरिक श्रम करने में असमर्थ है, लेकिन किसी संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को विशेष गृह में सौंपने की सजा सुनाएगा।

(4)यदि चिकित्सा अधिकारी रिपोर्ट करता है कि उक्त व्यक्ति किसी संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित है, तो न्यायालय ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित घर में सौंपने की सजा सुनाएगा।

8. प्रमाणित संस्था से भागने की सजा.

- जो कोई भी उस प्रमाणित संस्थान से भाग जाएगा जिसमें उसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषसिद्धि पर उस अवधि की समाप्ति से पहले दोषी ठहराया गया है जिसके लिए उसे प्रतिबद्ध किया गया है, वह कारावास से दंडनीय होगा जिसे तीन महीने तक बढ़ाया जा सकता है।

9. भीख मांगने के लिए व्यक्तियों को नियोजित करने पर जुर्माना।

- जो कोई किसी व्यक्ति को भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के लिए नियोजित करता है या कराता है, या जिसके पास किसी बच्चे की अभिरक्षा, प्रभार या देखभाल है, वह रोजगार में शामिल होता है या उसे प्रोत्साहित करता है या किसी बच्चे को भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है या जो कोई किसी अन्य व्यक्ति का उपयोग करता है भीख मांगने के उद्देश्य से प्रदर्शन करने पर दोषी पाए जाने पर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो एक साल से कम नहीं होगी।

10. बांड.

- दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय XLII के प्रावधान, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के तहत लिए गए बांड पर लागू होंगे।

11. अपील.

- इस अधिनियम के तहत किए गए हिरासत के किसी भी आदेश के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के भाग VII में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अपील या पुनरीक्षण किया जाएगा। हिरासत की अवधि को उसी अवधि के लिए कारावास की सजा माना जाएगा।

12. मुक्त करने की शक्ति.

- यदि राज्य सरकार किसी भी समय, अपनी स्वयं की प्रेरणा से या उसे किए गए आवेदन पर संतुष्ट है कि धारा 4 और धारा 5 के तहत दोषी ठहराया गया और प्रमाणित संस्थान के लिए प्रतिबद्ध व्यक्ति बीमारी से ठीक हो गया है या स्वस्थ स्थिति में है यदि वह अपने जीवन यापन के लिए स्वस्थ है या अन्यथा उस अवधि की समाप्ति से पहले छुट्टी पाने के लिए उपयुक्त है जिसके लिए उसे प्रतिबद्ध किया गया है, तो राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस प्रकार हिरासत में लिए गए व्यक्ति को ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों के अधीन रिहा कर दिया जाएगा, यदि कोई भी, जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

13. स्वागत केन्द्र.

(1)राज्य सरकार ऐसे स्थान या स्थानों पर एक या अधिक रिसेप्शन सेंटर उपलब्ध करा सकती है और उनका रखरखाव कर सकती है, जैसा वह उचित समझती है, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी संस्थान को रिसेप्शन सेंटर होने के लिए प्रमाणित कर सकती है।

14. प्रमाणित संस्थाएँ।

(1)राज्य सरकार ऐसे स्थान या स्थानों पर एक या अधिक प्रमाणित संस्थान उपलब्ध करा सकती है और बनाए रख सकती है, जैसा वह उचित समझती है, और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी भी संस्थान को प्रमाणित संस्थान होने के लिए प्रमाणित कर सकती है। ऐसा कोई भी प्रमाणित संस्थान कृषि, औद्योगिक और अन्य गतिविधियों की शिक्षा और कैदियों की सामान्य शिक्षा और चिकित्सा देखभाल भी प्रदान कर सकता है।

(2)प्रत्येक प्रमाणित संस्थान और रिसेप्शन सेंटर एक अधीक्षक के प्रभार में होगा।

15. रिसेप्शन सेंटरों और प्रमाणित संस्थानों में खोजें।

- एक रिसेप्शन सेंटर या प्रमाणित संस्थान का अधीक्षक आदेश दे सकता है कि रिसेप्शन सेंटर या प्रमाणित संस्थान में प्राप्त किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जाएगी, उसे साफ किया जाएगा, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जाएगा, और उक्त के साथ या उसके पास कोई भी पैसा या कीमती सामान पाया जाएगा। व्यक्ति को ऐसे अधीक्षक की हिरासत में रखा जाएगा, और धन या कीमती सामान के अलावा कोई भी सामान पाए जाने पर निर्धारित तरीके से निपटान किया जाएगा। जहां न्यायालय द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति के खिलाफ हिरासत का आदेश पारित किया जाता है, अधीक्षक आदेश दे सकता है कि उक्त व्यक्ति के पास या उसके पास पाए गए किसी भी धन या कीमती सामान का निर्धारित तरीके से निपटान किया जाएगा। जहां न्यायालय ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में हिरासत के आदेश के अलावा कोई अन्य आदेश पारित करता है, तो उसका पैसा और कीमती सामान उसे वापस कर दिया जाएगा और यदि उसके कपड़े नष्ट हो गए हैं, तो उसे नए कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे। ऐसे कपड़े उपलब्ध कराने का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा:बशर्ते कि किसी महिला की तलाशी केवल महिला द्वारा ही शालीनता के साथ की जाएगी।

16. प्रबंधन और अनुशासन.

- इस अधिनियम के तहत रिसेप्शन सेंटरों और प्रमाणित संस्थानों में भेजे गए या हिरासत में लिए गए व्यक्ति प्रबंधन और अनुशासन के ऐसे नियमों के अधीन होंगे, जिनमें मैनुअल या अन्य कार्य करना और समय-समय पर निर्धारित दंड देना शामिल है।

17. अनुशासनात्मक कारावास.

- तुरंत पूर्ववर्ती धारा के तहत की जाने वाली किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक या अधीक्षक किसी प्रमाणित संस्थान में हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति के मामले की रिपोर्ट न्यायालय को कर सकते हैं जो जानबूझकर किसी नियम का पालन करने में अवज्ञा या उपेक्षा करता है। उस अनुभाग में संदर्भित; और इसके बाद न्यायालय, यदि संतुष्ट हो जाता है कि उक्त व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसे किसी नियम का पालन करने में अवज्ञा की है या उपेक्षा की है, तो प्रमाणित संस्थान या उसके हिस्से में उसकी हिरासत की अवधि के शेष को कारावास की अवधि में परिवर्तित कर सकता है।

18. मुख्य निरीक्षक एवं अन्य प्राधिकारियों की नियुक्ति.

(1)इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार प्रमाणित संस्थानों के एक मुख्य निरीक्षक, निरीक्षकों और उतनी संख्या में सहायक निरीक्षकों और परिवीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है, जितनी वह मुख्य निरीक्षक की सहायता के लिए उचित समझे, और प्रत्येक व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक की सहायता के लिए नियुक्त कर सकती है। उसके पास शक्तियां होंगी और वह मुख्य निरीक्षक के ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, लेकिन वह मुख्य निरीक्षक के निर्देशों के तहत कार्य करेगा।

(2)प्रत्येक प्रमाणित संस्थान का प्रत्येक छह महीने में कम से कम एक बार मुख्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

19. एक रिसेप्शन सेंटर या प्रमाणित संस्थान से दूसरे में स्थानांतरण।

(1)निर्धारित शर्तों के अधीन, मुख्य निरीक्षक रिसेप्शन सेंटर या प्रमाणित संस्थान में हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को वहां से राज्य के किसी अन्य रिसेप्शन सेंटर या प्रमाणित संस्थान में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकता है:बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति की हिरासत की कुल अवधि ऐसे स्थानांतरण से किसी भी स्थिति में नहीं बढ़ेगी।

(2)इस तरह के स्थानांतरण का निर्देश देते समय मुख्य निरीक्षक को धारा 23 के तहत राज्य सरकार या न्यायालय द्वारा दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र और निर्देशों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखना होगा।

20. लाइसेंस पर रिलीज.

(1)ऐसी शर्तों के अधीन, जो निर्धारित की जा सकती हैं -(ए)प्रमाणित संस्थान के मुख्य निरीक्षक या अधीक्षक किसी भी समय किसी प्रमाणित संस्थान में हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छोटी अवधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुमति दे सकते हैं, और(बी)मुख्य निरीक्षक किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को सशर्त रिहा कर सकता है और उसे इसके लिए लाइसेंस जारी कर सकता है।

(2)ऐसा कोई भी लाइसेंस उस अवधि की समाप्ति तक लागू रहेगा जिसके लिए व्यक्ति को प्रमाणित संस्थान में हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था, जब तक कि इसे जल्द ही रद्द नहीं किया जाता।

(3)वह अवधि जिसके दौरान ऐसा व्यक्ति उपरोक्त अनुमति या लाइसेंस द्वारा किसी प्रमाणित संस्थान से अनुपस्थित रहता है, प्रमाणित संस्थान में उसकी हिरासत की अवधि की गणना के उद्देश्य से, उसकी हिरासत का हिस्सा माना जाएगा।

21. लाइसेंस का निरसन.

(1)ऐसी शर्तों के अधीन जो निर्धारित की जा सकती हैं, मुख्य निरीक्षक किसी भी समय धारा 20 के तहत जारी लाइसेंस को रद्द कर सकता है, और उसके बाद रिहा किए गए व्यक्ति को उस अवधि की समाप्ति तक एक प्रमाणित संस्थान में हिरासत में रखा जाएगा जिसके लिए उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था। .

(2)इस धारा के प्रयोजन के लिए, मुख्य निरीक्षक, यदि आवश्यक हो, रिहा किए गए व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और हिरासत के आदेश की एक प्रति के साथ निकटतम रिसेप्शन सेंटर में भेज सकता है, और उसके बाद उप-धारा (1) के प्रावधान धारा 22 लागू हो सकती है.

22. निरोध या कारावास की सजा के आदेश पर प्रक्रिया.

(1)उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन, जब किसी व्यक्ति को धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के तहत किसी प्रमाणित संस्थान में हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है, तो हिरासत का आदेश देने वाला न्यायालय उसे तुरंत निकटतम रिसेप्शन सेंटर में भेज देगा। हिरासत के आदेश की एक प्रति. इसके बाद व्यक्ति को रिसेप्शन सेंटर के अधीक्षक की हिरासत में सौंप दिया जाएगा और रिसेप्शन सेंट्रल में तब तक हिरासत में रखा जाएगा जब तक कि उसे वहां से किसी प्रमाणित संस्थान में नहीं भेज दिया जाता।

(2)जब ऐसे किसी व्यक्ति को धारा 5, या धारा 17 की उप-धारा (3) के तहत कारावास की सजा सुनाई गई है, तो कारावास की सजा सुनाने वाला न्यायालय तुरंत उस जेल में एक वारंट भेज देगा जिसमें उसे कैद किया जाना है और उसे अग्रेषित करना होगा। हिरासत के आदेश की एक प्रति के साथ वारंट के साथ उसे ऐसी जेल में भेजा जाएगा। कारावास की सजा पूरी तरह से निष्पादित होने के बाद, इसे निष्पादित करने वाला अधिकारी, यदि किसी प्रमाणित संस्थान में किसी भी अवधि के लिए हिरासत में रहना बाकी है, तो हिरासत के आदेश की एक प्रति के साथ उसे तुरंत निकटतम रिसेप्शन सेंटर को भेज देगा। और उसके बाद उपधारा (1) के प्रावधान लागू होंगे।

(3)उस अवधि की गणना करने में जिसके लिए किसी व्यक्ति को प्रमाणित संस्थान में हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है, इस धारा के तहत वह अवधि भी शामिल होगी जिसके लिए उसे रिसेप्शन सेंटर में हिरासत में रखा गया है।

23. कुष्ठ रोगियों एवं पागलों की चिकित्सीय जांच एवं निरोध।

(1)जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि न्यायालय के किसी आदेश के तहत प्रमाणित संस्थान में हिरासत में लिया गया कोई भी भिखारी विकृत दिमाग का है या कोढ़ी है, तो राज्य सरकार किसी भी आदेश द्वारा विश्वास के आधार बता सकती है कि भिखारी मानसिक रूप से

विकृत है या किसी कोढ़ी को मानसिक अस्पताल या कुष्ठरोग आश्रय या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान पर ले जाने का आदेश दिया जाता है, जहां उस अवधि की शेष अवधि के दौरान राज्य सरकार के निर्देशानुसार रखा जाएगा और उसके साथ व्यवहार किया जाएगा, जिसके लिए उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है या यदि हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। उस अवधि की समाप्ति पर एक चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि भिखारी या अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि उसे चिकित्सा देखभाल या उपचार के तहत आगे हिरासत में रखा जाए, उसे तब तक हिरासत में रखा जाए जब तक कि उसे कानून के अनुसार छुट्टी नहीं मिल जाती।

(2)जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि भिखारी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया है, या कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है, राज्य सरकार, यदि वह अब हिरासत में रखे जाने के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो उसे रिहा करने का आदेश देगी। यदि भिखारी अभी भी हिरासत में रखे जाने के लिए उत्तरदायी है, तो राज्य सरकार, भिखारी का प्रभार रखने वाले व्यक्ति को निर्देशित एक आदेश द्वारा, उसे प्रमाणित संस्थान में भेज देगी जहां से उसे हटा दिया गया था।

(3)भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा 31 के प्रावधान और कुष्ठ रोग अधिनियम, 1898 की धारा 14 के प्रावधान, समाप्ति के बाद उप-धारा (1) के तहत मानसिक अस्पताल या कुष्ठ आश्रम में बंद प्रत्येक भिखारी पर लागू होंगे। वह अवधि जिसके लिए उसे हिरासत में रखने का आदेश दिया गया था; और वह समय जिसके दौरान एक भिखारी को उस उपधारा के तहत मानसिक अस्पताल या कुष्ठ आश्रम में कैद किया जाता है, उस अवधि के हिस्से के रूप में गिना जाएगा जिसके लिए उसे अदालत द्वारा हिरासत में लेने का आदेश दिया गया हो सकता है:बशर्ते कि जहां दिमागी तौर पर अस्वस्थता या कुष्ठ रोग के कारण किसी भिखारी को हटाना तत्काल आवश्यक हो, वहां उस संस्था के अधिकारियों के लिए यह खुला होगा जिसमें भिखारी को हिरासत में लिया गया है, वह भारतीय पागलपन अधिनियम, 192 के तहत अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में आवेदन कर सकता है या कुष्ठ रोग अधिनियम, 1898, जैसा भी मामला हो, उसे मानसिक अस्पताल या कुष्ठ आश्रम में भेजने के तत्काल आदेश के लिए।

24. प्रमाणित संस्थानों के बीच स्थानांतरण.

(1)राज्य सरकार किसी प्रमाणित संस्थान में हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को वहां से भारत के किसी अन्य हिस्से में समान प्रकृति के किसी संस्थान में स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकती है, जिसके संबंध में हरियाणा राज्य के समान प्रावधान वहां की राज्य सरकार द्वारा किया गया है। उसमें लागू किसी भी कानून के तहत भाग:बशर्ते कि इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति

को उस दूसरे राज्य की सरकार की सहमति के बिना किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(2)राज्य सरकार, किसी प्रमाणित संस्थान के अधीक्षक के परामर्श से किसी भी व्यक्ति को उस संस्थान में स्थानांतरित करने की सहमति दे सकती है जिसके संबंध में भारत के किसी अन्य हिस्से में किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिरासत की प्रकृति का आदेश दिया गया है। इस अधिनियम के तहत दिए गए आदेश में उसे एक प्रमाणित संस्थान या समान प्रकृति के संस्थान में हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया है और ऐसे स्थानांतरण पर इस अधिनियम के प्रावधान ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे।

25. पशुओं की जब्ती और निपटान.

(1)कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति धारा 3 की उपधारा (1) के तहत, भीख मांगते हुए पाए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी करते हुए किसी भी जानवर को जब्त कर सकता है जिसके घाव, घाव, चोट, विकृति या बीमारी उजागर या प्रदर्शित की गई हो। भिक्षा मांगने या प्राप्त करने के उद्देश्य वाला व्यक्ति।

(2)जब्ती करने वाला पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति ऐसे जानवर को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1980 की धारा 35 के तहत नियुक्त किसी भी अस्पताल में उप-धारा (3) के तहत न्यायालय के आदेशों तक हिरासत में रखने के लिए ले जा सकता है;बशर्ते कि यदि दूसरा व्यक्ति सुविधाजनक समझे तो वह जब्त किए गए जानवर को पुलिस अधिकारी को सौंप सकता है।

(3)वह न्यायालय, जिसके समक्ष भीख मांगते हुए पाए गए व्यक्ति को लाया गया है, निर्देश दे सकता है कि पशु का ऐसे अस्पताल में इलाज और देखभाल की जाएगी जब तक कि वह छुट्टी के लिए उपयुक्त न हो जाए या उसे पिंजरापोल भेज दिया जाए, या यदि पशु चिकित्सा अधिकारी प्रभारी हो। जिस क्षेत्र में जानवर पाया जाता है या ऐसा कोई अन्य पशु चिकित्सा अधिकारी, जिसे पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1890 की धारा 15 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा अधिकृत किया गया है, प्रमाणित करता है कि यह लाइलाज है या क्रूरता के बिना इसे हटाया नहीं जा सकता है, कि इसे हटा दिया जाएगा। नष्ट किया हुआ; और न्यायालय यह भी आदेश दे सकता है कि अस्पताल से रिहाई के बाद जानवर को जब्त किया जा सकता है।

(4)किसी अस्पताल में देखभाल और उपचार के लिए भेजे गए जानवर को, जब तक कि अदालत यह निर्देश न दे कि इसे पिंजरापोल में भेजा जाएगा या इसे नष्ट कर दिया जाएगा, तब तक ऐसी जगह से नहीं छोड़ा जाएगा, सिवाय इसके कि पशुचिकित्सा द्वारा जारी किए गए डिस्चार्ज के लिए इसकी उपयुक्तता का प्रमाण पत्र दिया जाए। उस क्षेत्र का प्रभारी अधिकारी जिसमें रुग्णालय

स्थित है या ऐसा अन्य पशु चिकित्सा अधिकारी जो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1890 की धारा 15 के तहत बनाए गए नियमों द्वारा अधिकृत किया गया हो।

26. अपराधों का संज्ञेय और गैर-जमानती होना।

- इस अधिनियम की धारा 5 और 9 के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

27. व्यक्तियों को लोक सेवक समझा जायेगा।

- इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्य को करने के लिए सशक्त सभी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का एक्सएलवी) के अर्थ के तहत लोक सेवक माना जाएगा।

28. विजिटिंग कमेटी.

- प्रत्येक प्रमाणित संस्थान के लिए, राज्य सरकार निर्धारित तरीके से एक विजिटिंग कमेटी नियुक्त करेगी और समिति को ऐसी शक्तियां, कर्तव्य और कार्य सौंपेगी जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

29. सलाहकार समिति.

(1)राज्य सरकार, पूरे राज्य या उसके किसी भाग के लिए, एक सलाहकार समिति का गठन कर सकती है जिसमें ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे, जिनकी संख्या ग्यारह से अधिक नहीं होगी, जिन्हें वह नियुक्त कर सकती है:बशर्ते कि, जहां एक स्थानीय प्राधिकारी प्रमाणित संस्थानों के रखरखाव के लिए ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो, जिसे राज्य सरकार प्रत्येक मामले में उचित समझे, जिसमें स्थानीय प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के अधीन क्षेत्र के भिखारियों को हिरासत में लिया जाता है, राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे क्षेत्र के लिए सलाहकार समिति में उतनी संख्या में व्यक्तियों को नियुक्त करेगी जितनी वह उचित समझेगी।

(2)किसी भी क्षेत्र में उपधारा (1) के तहत गठित सलाहकार कॉमडेक्स या उसका कोई भी सदस्य हर उचित समय पर किसी भी प्रमाणित संस्थान का दौरा कर सकता है, जिसमें उस क्षेत्र के भिखारियों को हिरासत में लिया जाता है।

(3)सलाहकार समिति यह भी कर सकती है –

(ए)मुख्य निरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य अधिकारी के माध्यम से किसी प्रमाणित संस्थान के प्रबंधन के संबंध में निविदा सलाह;

(बी)स्थानीय क्षेत्र के भीतर या जहां उस क्षेत्र के भिखारियों को हिरासत में लिया गया है, किसी या सभी प्रमाणित संस्थानों के आवर्ती और साथ ही गैर-आवर्ती खर्चों के लिए सदस्यता एकत्र करना, और निर्धारित तरीके से संग्रह का वितरण करना;

(सी)किसी संस्थान को प्रमाणित संस्थान के रूप में प्रमाणित करने या क्षेत्र के भीतर किसी प्रमाणित संस्थान को अप्रमाणित करने के संबंध में मुख्य निरीक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सलाह देना; और

(डी)राज्य सरकार को आम तौर पर उस क्षेत्र में इस अधिनियम के कामकाज पर और विशेष रूप से मुख्य निरीक्षक या राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी द्वारा संदर्भित किसी भी बिंदु पर सलाह देना।

30. इस अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई का संरक्षण.

- इस अधिनियम के तहत कोई भी कार्य करने के लिए सशक्त किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी, जो इस अधिनियम के तहत अच्छे विश्वास में किया गया हो या करने का इरादा हो।

31. नियम बनाने की शक्ति.

(1)राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन की शर्तों के अधीन, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

(2)विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं, -

(ए)धारा 2 के खंड (ए) के तहत किसी उद्देश्य को अधिकृत करने का तरीका;

(बी)क्रमशः धारा 3 की उपधारा (1) या धारा 25 की उपधारा (1) के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों या जब्त किए गए जानवरों को रखने का तरीका;

(सी)धारा 4 की उपधारा (1) के तहत संक्षिप्त पूछताछ करने का तरीका;

(डी)धारा 5 और धारा 17 के तहत सजा पाए व्यक्ति किस तरह और किस स्थान पर कारावास की अवधि काटेंगे;

(इ)भिखारियों की चिकित्सीय जांच का तरीका;

(एफ)वह तरीका जिसमें धारा 15 में निर्दिष्ट प्रभाव और धन और क़ीमती सामान का निपटान किया जाएगा;

(जी)प्रमाणित संस्थानों का प्रबंधन, उनके लिए प्रतिबद्ध व्यक्तियों की हिरासत और उनके श्रम और सामान्य आचरण से संबंधित सभी मामलों सहित ऐसे व्यक्तियों का रखरखाव, देखभाल, उपचार और निर्देश;

(एच)रिसेप्शन सेंटर या प्रमाणित संस्थान में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का प्रबंधन और अनुशासन, जिसमें मैनुअल या अन्य कार्य लगाना और इस खंड के तहत बनाए गए किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए सजा देना शामिल है;

(मैं)धारा 18 के तहत नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(जे)वे शर्तें जिनके अधीन मुख्य निरीक्षक धारा 19 के तहत स्थानांतरण का निर्देश दे सकता है;

(क)वे शर्तें जिनके अधीन किसी व्यक्ति को धारा 20 के तहत लाइसेंस पर रिहा किया जा सकता है;

(एल)वे शर्तें जिनके अधीन धारा 21 के तहत लाइसेंस रद्द किया जा सकता है;

(एम)प्रमाणित संस्थानों से व्यक्तियों का निष्कासन;

(एन)किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए या ऐसे संस्थानों के बाहर किसी भी रोजगार को स्वीकार करने में विफलता या उपेक्षा के लिए प्रमाणित संस्थानों में हिरासत में लिए गए व्यक्तियों पर लगाए जाने वाली सजा की प्रकृति, घटनाएं और अधिकतम अवधि, जो उनके लिए सुरक्षित हो सकती है;

(ओ)धारा 28 के तहत विजिटिंग कमेटी नियुक्त करने का तरीका और उसकी शक्तियां, कर्तव्य और कार्य;

(पी)विजिटिंग और सलाहकार समितियों की नियुक्ति और ऐसी समितियों की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों का असाइनमेंट; और

(क्यू)कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना है या किया जा सकता है।

(3)इस धारा के तहत बनाए गए किसी भी नियम में यह प्रावधान हो सकता है कि इसका उल्लंघन करने पर कारावास की सजा हो सकती है, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

(4)इस धारा के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा, जबकि यह सत्र में कुल दस दिनों की अवधि के लिए होगा, जिसमें एक सत्र या दो या अधिक क्रमिक सत्र शामिल हो सकते हैं। और यदि, जिस सत्र में इसे रखा गया है या उपरोक्त लगातार सत्रों की समाप्ति से पहले, सदन नियम में कोई संशोधन करने पर सहमत होता है या सदन इस बात पर सहमत होता है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो नियम उसके बाद ही प्रभावी होगा ऐसे संशोधित रूप में या प्रभावहीन होना, जैसा भी मामला हो;

हालाँकि, ऐसा कोई भी संशोधन या रद्दीकरण नियम के तहत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

32. कठिनाइयों का निवारण.

- यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसा प्रावधान कर सकती है या ऐसा निर्देश दे सकती है जो उसे ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हो।